

क्या ट्रंप अमेरिकी शिक्षा मंत्रालय करेंगे बंद, शिक्षा प्रणाली में होगा बदलाव

वॉशिंगटन

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं ट्रंप प्रशासन अमेरिकी शिक्षा मंत्रालय बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में संघीय शिक्षा विभाग की आलोचना की थी और इसे कट्टरपंथी नोकरशाही बताया था। ट्रंप का कहना है कि यह मंत्रालय अमेरिकी परिवारों के जीवन में हस्तक्षेप करता है और इस पर उनके विचारों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अब

इसका उद्देश्य कॉलेज शिक्षा सस्ती और अधिक सुलभ बने

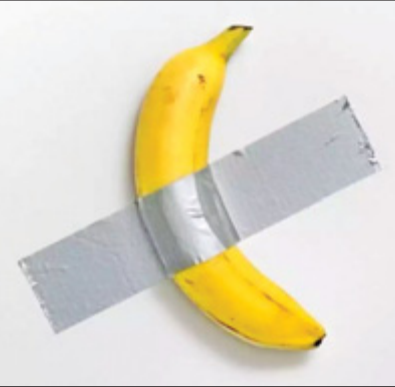
ट्रंप ने पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई सीईओ और पेशेवर रेस्लर लिंडा मैकमोहन को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आ सकता है। उनके दृष्टिकोण के मुताबिक शिक्षा के मामले में

केंद्रीय स्तर पर फैसले लेने की बजाय राज्य स्तर पर नियंत्रण होना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि इससे ज्यादा प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बेहतर तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि राज्य सरकारों को शिक्षा से संबंधित सभी फैसला लेने का अधिकार मिले, ताकि स्कूलों की नीतियां और पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के प्रभाव से बाहर रह सकें। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका में बच्चों पर जो खर्च

किया जाता है, वह अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी परिणाम संतोषजनक नहीं होते। वह इस समस्या का समाधान राज्य स्तर पर शिक्षा नीति को नियंत्रित करके करना चाहते हैं। इसके अलावा, ट्रंप का उद्देश्य है कि कॉलेज शिक्षा सस्ती और अधिक सुलभ बने, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को डिग्री मिल सके। वह चाहते हैं कि अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में देशभक्ति और पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए।

न्यूज़ ब्रीफ

52.38 करोड़ में बिका दीवार पर चिपकाया एक केला



न्यूयॉर्क। अमेरिका में दीवार पर काली टेप से चिपकाया गया एक केला करोड़ों रुपये में बिक गया। कलाकार ने इस कला-कृति को कॉर्मेडियन नाम दिया गया है। इस केले को इटालियन कलाकार मॉरिजियो कैटेलन ने तैयार किया था। सौथबीज ऑक्शन उडएस में आयोजित नीलामी में यह केला लगभग 52.38 करोड़ रुपये में बिका। इसे मशहूर क्रिप्टोकरंसी एंटरप्रेन्योर जस्टिन सन ने खरीदा। यह आर्टवर्क पहली बार 2019 में मियामी में पेश किया गया था, लेकिन इस बार इसकी कीमत ने सभी को हैरान कर दिया। नीलामी के दौरान पांच मिनट तक चली बोली में जस्टिन सन ने छह अन्य दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए इसे खरीदा। दिलचस्प बात यह है कि नीलामी के लिए रखे जाने से पहले यह केला मात्र 0.35 डॉलर (लगभग 30 रुपये) में खरीदा गया था। जस्टिन सन ने इसे खरीदने के बाद कहा कि यह कला-कृति आधुनिक संस्कृति, मीम्स और क्रिप्टोकरंसी समुदाय को जोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व बताया, जो कला और उपभोक्तावाद के बीच की सीमाओं को धुंधला करता है। इस केले की ऊंची कीमत ने इसे दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक बना दिया है। यह आर्टवर्क इस बात पर सवाल उठाता है कि कला का असली मूल्य उसकी सामग्री में है या उसके विचार में। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉर्मेडियन जैसी कृतियां पारंपरिक कला की सीमाओं को तोड़ती हैं और नई सोच को बढ़ावा देती हैं। हालांकि, कई लोगों ने इस नीलामी को आलोचना का विषय भी बनाया है।

प्यार के लिए हर हफ्ते जाता था चीन से आस्ट्रेलिया प्रेमी, पलाइटर पर खर्च की लाखों



बीजिंग। इंसान प्यार के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। ऐसा ही उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला यहां पढ़ाई कर रहे एक चीनी व्यक्ति ने अपने प्यार के लिए किया है। यह शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने हर हफ्ते चीन से ऑस्ट्रेलिया से जाता था और ऐसा उसने लगातार तीन महीनों तक किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल का गुआंगली ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आरएमआईटी विश्वविद्यालय में आर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। उसका घर चीन के शांदोंग प्रांत में है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है। जू की गर्लफ्रेंड ने भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की थी और काले पुरा हो जाने के बाद वापस चीन लौट गई, जिसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक तीन महीनों के लिए गुआंगली को चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप-डाउन करना पड़ा क्योंकि उसे हफ्ते में केवल एक दिन क्लास अटेंड करनी होती थी। इस दौरान गुआंगली मेलबर्न के लिए उड़ान भरता था, अगले दिन क्लास में शामिल होता था और उसे अगले दिन चीन के लिए रवाना हो जाता था। ऐसे ही अगस्त से अक्टूबर तक गुआंगली ने 11 हफ्तों तक यात्रा की और अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताया जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चीन लौट आई थी। गुआंगली की यात्रा सुबह 7 बजे उसके होम टाउन देझोऊ से शुरू होती थी जहां से वह पलाइड पकड़ने के लिए जिनान जाता था। एक जगह रुकने के बाद वह अगले दिन क्लास के लिए मेलबर्न पहुंचता था और तीसरे दिन घर लौट आता था। मीडिया रिपोर्ट में यह हमेरा आखिरी सेमेस्टर था और मुझे ग्रेजुएशन के लिए केवल एक क्लास करनी होती थी। इससे भी जरूरी बात यह थी कि मेरी गर्लफ्रेंड चीन लौट गई थी और मेलबर्न में मेरी अकेली सी थी। आठ सालों से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे गुआंगली ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि उनके इस फैसले से उन्हें चीन के डोमेस्टिक वर्क कल्चर को भी देखने का अवसर मिला, जिससे प्युचर में उनके करियर में फायदा हो सकता है। एक वीडियो में गुआंगली ने प्रत्येक यात्रा की लागत का ब्योरा भी दिया जो कुल 6700 युआन थी, जिसमें 4700 युआन की वापसी की पलाइट टिकट, टैक्सी किराया और खाना-पीना भी शामिल था। मेलबर्न में हर हफ्ते एक रात के दौरान वह पैसे बचाने के लिए एक दोस्त के घर पर रुकता था। हालांकि, यह मेलबर्न में पहले दिए जाने वाले 10,000 युआन के उसके मासिक किराए से ज्यादा था फिर भी उसने कहा कि प्यार के लिए और घर के अच्छे खाने के लिए खर्च किया गया यह समय और पैसा सार्थक था। गुआंगली ने अपनी यात्राओं का ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी किया, जिससे सोशल मीडिया पर उसके करीब 10 हजार फॉलोअर्स बन गए। उसकी कहानी ने सोशल मीडिया यूजर्स को चौंका दिया है, जिन्होंने उसकी लगन और सहनशक्ति की तारीफ की है।

पुतिन का जंगी प्लान : 13 हजार किमी की रफ्तार और 15 मिनट में टारगेट खत्म

कीव

यूक्रेन द्वारा की गई जांच से पता चला है कि यूक्रेनी शहर दिनप्रो पर हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की हाईएस्ट स्पीड 13,000 किमी/घंटा थी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल को टारगेट (यूक्रेनी सैन्य सुविधा) तक पहुंचने में केवल 15 मिनट लगे। यूक्रेन की सेना के मुख्य खुफिया निदेशालय (एचयूआर) ने खुलासा किया, अस्त्रखान क्षेत्र में लॉन्च होने के क्षण से लेकर दिनप्रो शहर में इसके प्रभाव तक इस रूसी मिसाइल का उड़ान समय 15 मिनट था। मिसाइल छह वारहेड से लैस थी: प्रत्येक में छह सबम्युनिशन लगे थे। प्रक्षेप पथ के अंतिम भाग में गति मैक 11 से अधिक थी। यूक्रेन और रूस, दोनों देश रह-रहकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उम्मीद जगी थी कि रूस और यूक्रेन जंग का हल निकलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार (22 नवंबर) को दावा किया कि रूस की हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल, जिसे गुरुवार को यूक्रेन पर दागा गया था, को ट्रैक करके मार गिराया नहीं जा सकता। उन्होंने मिसाइल के सीरियल उत्पादन की शुरुआत का भी आदेश दिया है। उनके इस आदेश से साफ लग रहा है कि वह यूक्रेन को खत्म करने के ही मूड में हैं। पुतिन ने कहा है कि मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में ऐसी मिसाइल का कोई जवाबी उपाय नहीं है, इसे रोकने का कोई साधन नहीं है। और मैं एक बार फिर इस बात पर जोर दूंगा कि हम इस लेटेस्ट सिस्टम का टेस्ट जारी रखेंगे। इसका सीरियल उत्पादन स्थापित करना आवश्यक है। अपने सैन्य प्रमुखों के साथ टेलीविजन



फ्रांस और नॉर्वे ने इजरायल पर आईसीसी की कार्रवाई का किया समर्थन, सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ पर गाजा और इजरायल क्षेत्रों में युद्ध अपराध करने का आरोप है

पेरिस। फ्रांस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हम्रास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का समर्थन किया है। आईसीसी के प्री-ट्रायल चैंबर ने नेतन्याहू और गैलेंट पर अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए हैं। मोहम्मद देफ पर गाजा और इजरायल के क्षेत्रों में युद्ध अपराध करने का आरोप है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थिरता की गारंटी है और इसके आदेशों का पालन आवश्यक है। फ्रांस ने स्पष्ट किया कि वह दंड से मुक्ति के खिलाफ संघर्ष को अपनी प्राथमिकता मानता है। हालांकि जब नेतन्याहू की संभावित गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया, तो प्रवक्ता ने इसे कानूनी रूप से जटिल बताते हुए कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। साथ ही फ्रांस ने गाजा और लेबनान में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, जो हालिया युद्धों में क्षतिग्रस्त हुई हैं। नॉर्वे ने भी आईसीसी की कार्रवाई का समर्थन करते हुए इसे गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम बताया। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईंडे ने कहा कि आईसीसी निष्पक्ष सुनवाई मानकों के तहत कार्रवाई करेगा। यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव को और बढ़ा सकता है, जबकि न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग तेज हो रही है।



वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के कोरोना की संरचना और आकार का पता लगाया

वॉशिंगटन

हाल ही में हुए एक अध्ययन ने सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाले सूर्य के चमकीले प्रभामंडल के ब्लैक होल के इस कोरोना की संरचना और आकार का पता लगाया है। ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल का डोनट के आकार का एक टोरस होता है, जिसके भीतर एक्रीशन डिस्क मौजूद होती है। यह डिस्क अत्यधिक गर्म पदार्थ से बनी होती है, जो ब्लैक होल की ओर प्रवाहित होती है। डिस्क का सबसे भीतरी हिस्सा, जहां तापमान अरबों डिग्री तक पहुंच सकता है, ब्लैक होल का कोरोना माना जाता है। सूर्य के कोरोना की तरह, ब्लैक होल का कोरोना भी ऊर्जा विकिरण करता है, लेकिन इसका तापमान कहीं अधिक होता है। यही कारण है कि इसका प्रकाश एक्रीशन डिस्क की रोशनी में छिपा रहता है। शोधकर्ताओं ने ब्लैक होल के कोरोना का पता लगाने के लिए नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलीरिमेट्री एक्सप्लोरर के डेटा का उपयोग किया। उन्होंने मिलकी वे और लार्ज मैंगेलेनिक क्लाउड में स्थित ब्लैक होल जैसे सिग्नस एक्स-1 और एक्स-3 का अध्ययन किया। इन ब्लैक होल से उत्सर्जित एक्स-रे, टोरस में बिखरते और हमारी दृष्टि में परावर्तित होते हैं। अध्ययन ने दिखाया कि ब्लैक होल का कोरोना, सूर्य के कोरोना की तरह गोले में घेरने



के बजाय, एक डिस्क के रूप में एक्रीशन डिस्क को घेरता है। यह खोज न केवल ब्लैक होल के मॉडल को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि यह भी समझने में सहायक होगी कि ब्लैक होल पदार्थ को कैसे निगलते हैं और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस को शक्ति कैसे प्रदान करते हैं। यह शोध खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लैक होल के कोरोना की संरचना को समझने से उन प्रक्रियाओं का पता चलेंगा जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय वस्तुओं को संचालित करती हैं। साथ ही, यह हमारे ब्रह्मांडीय मॉडल को और सटीक बनाएगा, जिससे गहरी अंतरिक्ष खोज में नई संभावनाएं खुलेंगी। बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाले सूर्य के चमकीले प्रभामंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से आकर्षित किया है।

नेपालः काठमांडू महानगरपालिका ने पीएम ओली की पार्टी पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

काठमांडू

काठमांडू की महानगरपालिका ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ओली की पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम वाले स्थल पर गंदगी फैलाने के मामले में लगाया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शरीक हुए थे। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही मेयर बालेन शाह की तरफ से ओली की पार्टी नेकपा एमाले पर जुर्माना लगाए जाने के लिए लिखित पत्र भेज दिया गया। इसे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मेयर बालेन शाह के बीच कुछ समय से जारी शीतयुद्ध के रूप में भी देखा जा रहा है।

दरअसल, शनिवार को काठमांडू के



दरबरमार्ग में सत्तारूढ़ दल एमाले की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। इस समेलन की वजह से सार्वजनिक स्थल पर काफी गंदगी फैलने



के कारण महानगरपालिका की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। काठमांडू महानगरपालिका की तरफ से एमाले पार्टी के अध्यक्ष यानि केपी शर्मा

वॉशिंगटन

बिजनेस टाइकून गौतम अडानी फिर मुश्किलों से घिर गए हैं। इस बार अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी सहित आठ लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कारोबारी अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों से पैसे जुटाए और उन पैसों से भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की। ये रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई, जिससे 20 वर्षों में अडानी समूह की कंपनी को 2 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयां में करीब 16 हजार 881 करोड़ रुपये का मुनाफा होने का अनुमान है। लेकिन सवाल ये उठा रहा है कि भारतीय कारोबारी अडानी को लेकर क्या होगा।

क्या कहता है अमेरिकी कानून – दरअसल, अमेरिका में एफसीपीए नाम का कानून है, जिसे फॉर्न करप्ट प्रेवेंटीसाइज कानून कहते हैं। इसके तहत जो कंपनियां अमेरिका के प्रभाव एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उन पर कई तरह के निर्देश लागू होते



हैं। सबसे बड़ा निर्देश ये होता है कि वे दूसरे देशों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकते। लेकिन इस मामले में ठीक उलट हुआ। अमेरिका का कहना है कि इस कंपनी ने उसके निवेशकों को धोखा देकर जोखिम में डाला है। अभियोग में दावा किया गया है कि अडानी ग्रीन और एन्जोर के कर्ताधर्ताओं ने व्यावसायिक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर रिश्वत की पेशकश की। गौतम और सागर अडानी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी, साजिश के आरोप हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने भी उनके

खिलाफ एक दीवानी मामला दायर किया है। अडानी और उनके भतीजे सागर के लिए अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि अभियोजकों ने उन वारंटों को विदेशी कानून प्रवर्तन को सौंपने की योजना बनाई है।

वारंट जारी होने का क्या मतलब – दरअसल, अमेरिका में अभियोग का मतलब सिर्फ एक औपचारिक लिखित आरोप होता है जिसे एक अभियोजक (शिकायत कर्ता) द्वारा दर्ज होता है। उसके बाद ग्रैंड जूरी की तरफ से अपराध के आरोपों के खिलाफ अभियोग पत्र

जारी करती है। यानी अभियोग पत्र जारी होते ही आरोपी के खिलाफ स्वतः गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक, अभियोग पत्र के बाद अब कोर्ट में पूरे मामले में बहस होगी। अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष कोर्ट के पटल पर अपने-अपने सबूत रखेगा। हालांकि, अडानी अभी आरोपी हैं, इसलिए अमेरिका, भारत से प्रत्यर्पण की मांग नहीं कर सकता है। यह प्रक्रिया दोषी साबित होने के बाद आगे बढ़ेगी।

कौन-कौन आरोपी – जिन आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है, उसमें अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अडानी और अडानी ग्रीन कंपनी के एजीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी (30 वर्ष), अडानी ग्रुप के पूर्व सीईओ विनीत जैन का भी नाम है। इसके अलावा, रंजीत गुप्ता, रूथेश अग्रवाल भी आरोपी हैं।

केस में सिरिल केवेंनिज, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा की भूमिका का भी जाँच है। सागर अडानी, गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं।

एलन मस्क ने नेपाल के प्रधानमंत्री से स्टारलिक संचालन की अनुमति मांगी

काठमांडू। सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना में रहे एलन मस्क ने नेपाल में भी इसके संचालन के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए खुद मस्क ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है। एलन मस्क ने शुक्रवार देर रात प्रधानमंत्री ओली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस विषय पर बातचीत की। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने एक्स पर कहा कि एलन मस्क और उनके बीच नेपाल में स्टारलिक के जरिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने पर बातचीत हुई। ओली ने कहा कि सैटेलाइट के जरिए पूरे विश्व में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले एलन मस्क की टीम ने नेपाल में स्टारलिक के प्रयोग का डेमो भी दिखाया। मस्क ने नेपाल के प्रधानमंत्री से नेपाल में स्टारलिक के प्रयोग की अनुमति देने का आग्रह किया है। स्टारलिक की ग्लोबल लाइसेंसिंग एंड मार्केटिंग डायरेक्टर रेबेका स्किल हन्टर ने बताया कि मस्क ने प्रधानमंत्री ओली को स्टारलिक की तरफ से दिए जाने वाले सुविधा और सहूलियत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री ओली से स्टारलिक के नेपाल में रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ कानूनों में बदलाव करने का भी आग्रह किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया।